

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5336/2025

बुद्धू सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी अधिकारी एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है: "i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम वजीरपुर बी.ए., पोस्ट स्योहारा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर में स्थित गाटा संख्या 760 और 761 (क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर) की पैमाइश सुनिश्चित करें और भौतिक कब्जा सौंपें, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में हो, यानी सी.ओ. धामपुर द्वारा वाद संख्या 01/2021, चकबंदी अधिनियम की धारा 28 और 45 के तहत, बुद्धू सिंह एवं अन्य बनाम स्योनाथ सिंह एवं अन्य, ग्राम वजीरपुर बी.ए., पोस्ट स्योहारा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर में पारित आदेश दिनांक 29.06.2021, तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा वाद संख्या 460/2024, यू.पी. चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत, स्योनाथ सिंह बनाम बुद्धू सिंह में पारित आदेश दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन में हो।"
3. यह तर्क दिया गया है कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान, याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका के प्रार्थना खंड में उल्लिखित भूखंडों के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है; हालाँकि, आज तक, न तो उक्त भूखंडों का सीमांकन किया गया है और न ही उनका कब्जा उन्हें सौंपा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि ग्राम को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 52 के तहत वि-अधिसूचित कर दिया गया है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण यू.पी.सी.एच. नियमावली के नियम 109 के तहत अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।
5. चूंकि वर्तमान रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय मामले के गुणों में प्रवेश किए बिना या उस पर कोई टिप्पणी किए बिना इसे अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थना की गई है, याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ चकबंदी प्रक्रिया के दौरान चकबंदी न्यायालयों द्वारा पारित

आदेश के कार्यान्वयन के लिए यू.पी.सी.एच. नियमावली के नियम 109ए के तहत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करें। यदि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा नियम 109ए के तहत ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार शीघ्रता से उस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

विनय